International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 04, October - December, 2020, pp.93-100

वैश्वीकरण का भारत के विकास पर प्रभाव – मेक इन इण्डिया योजना के संदर्भ में

डॉ. पूनम तिवारी*

प्रस्तावना

भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। सितम्बर 2014 में ''मेक इन इण्डिया'' योजना का मूल उद्धेश्य भारत में नवीन टेक्नोलॉजी का विकास और भारत में ही बनाये जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य सिद्धान्त है कि विदेशी कम्पनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारत में ही उत्पादों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाये। मुख्यतः भारत को ''मैन्युफैक्चरिंग हब'' बनाने का इस योजना का उद्धेश्य रहा है।[1]

इस योजना में 25 क्षेत्रों का चयन किया गया है और अपेक्षा की गई है कि इन क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि की जावे। यह सब तभी सम्भव होगा जब अधिक से अधिक निवेश पर बल होगा। इसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार मिलेगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।[2]

प्रौधोगिक प्रतिस्पर्धा के युग में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित देशों की तुलना में कमजोर है। अतः मेक इन इण्डिया योजना के निर्माताओं ने यह स्वीकारा की भारत भी अर्थव्यवस्था हाथी की भाँति धीमी गति से चल रही है। हाथी चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, जो धीमी गति से चलता है। सन् 2014 में योजना निर्माताओं ने देश की औधोगिक व्यवस्था को गति देने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का प्रतीक हाथी के स्थान पर 'शेर' को स्वीकारा जो तेज गति से चलता है। अतः शेर की भांति औधोगिक विकास सम्भव होगा तो हम निश्चय ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे होंगे। यही सोच को ध्यान में रखते हुए ''मेक इन इण्डिया'' को अपनाया गया। पर कहा जा सकता है कि मेक इन इण्डिया भारतीय अर्थव्यवस्था का सम्बल प्रदान हेतु तथा वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत बनाने हेतु एक काल्पनिक प्रयास है।

वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करके एक नई विश्व व्यवस्था निर्मित करने वाली अवधारणा है। भारत में इसकी शुरूआत 90 में दशक से हुई लेकिन इसके पश्चात् इसने भारतीय समाज को व्यापक रूप से परिवर्तित किया। इस अवधारणा के भारतीय समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े।

भारतीय समाज अपनी मूल प्रकृति को छोड़कर वैश्विक प्रकृति में परिवर्तित हुआ जिसके कारण इसमें गतिशीलता तो आई लेकिन अपनी मूल प्रकृति का क्षरण भी हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था खुलने के कारण यहाँ के उत्पादों को विश्व में एवं बाहरी उत्पादों का यहाँ आयात–निर्यात होने लगा जिसके कारण भारतीय समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपी। भारत के संयुक्त परिवार टूटने लगे तथा एकल परिवार प्रणाली बढ़ी। परिवार टूटने के कारण वृद्धाश्रमों एवं 'बाल कल्याण केन्दों' की शुरूआत भारत में हुई। भारतीय समाज की भावनात्मक लगाव की प्रकृति समाप्त सी हो गई। भारत में तकनीक एवं नवाचार को बढ़ावा मिला, परिणाम स्वरूप सामाजिक जटिलता कम हुई तथा अन्धविश्वास का अंत हुआ। भारतीय परम्परागत उद्योगों की पुनः पहचान स्थापित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ हुई।

---

6 पी.डी.एफ, आई.सी.एस.एस.आर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

बहुराष्ट्रीय व घरेलू कंपनियों को भारत में ही अपने उत्पाद बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया। यह पहल न सिर्फ विनिर्माण, बल्कि प्रासंगिक आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्रों में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई। इस पहल का मुख्य दृष्टिकोण भारत में पूँजीगत व प्रौद्योगिको निवेश. दोनों को आकर्षित करना, ताकि देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकलकर दुनिया की सबसे अधिक एफडीआई वाला देश बन जाए।

इसका प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर देना था। इसमें ऑटोमोबाइल, उड्डयन जैव–पौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल व गैस, दवाई सम्मिलित हैं।

मेक इन इण्डिया का लोगो : इसकी प्रेरणा अशोक चक्र से ली गई है। इसमें लंबे डग भरता हुआ एक शेर है, जो दांतेदार पहियों से बना हुआ है। यह विनिर्माण, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संकेतक है।

इस पहल का एक और लक्ष्य है–उच्च गुणवत्ता वाले मानकों और स्थिरता के आयामों को लागू करना। इसमें अपनाई गई नीतियां हैं– कारोबार को आसान बनाना, पुराने पड़ चुके कानूनों से इनको दूर रखना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, पीएसयू कंपनियों का विनिवेश करना, युवाओं के लिए कौशल और रोजगार की व्यवस्था करना, इत्यादि! इन पहलों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं एक स्वस्थ कारोबारी माहोल को बनाना, गैर–अनुकूल कारकों को दूर करना, भारतीय एमएसएमई कंपनियों पर अधिक ध्यान देना, विश्व स्तरीय शोध व विकास की कमी को दूर करना और चीन के ''मेड इन चाइना'' अभियान से प्रतिस्पर्धा करना।[3]

यह पहल चार स्तंभों पर आधारित है– नई प्रक्रियाएं नए बुनियादी ढांचे, नए क्षेत्र और नई सोच। इस संदर्भ में भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

- सूचना के प्रसार के लिए और निवेशकों से वार्तालाप के लिए एक संवादमूलक पोर्टल का बनाया जाना जिसका उद्देश्य देश में निवेश अवसरों और परिदृश्य के बारे में जागरूक करना है, ताकि विदेशी बाजार में भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक एफडीआई में भारत की भागीदारी बढ़ सके।
- राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित और सरलीकृत करने की एंजेसी के रूप में इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना।
- देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्धेश्य के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट फसिलिटैशन सेल (निवेश प्रोत्साहन केन्द्र) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य काम है–सभी निवेश प्रश्नों को जानने–समझने में मदद करना, साथ ही संभावित निवेशकों की तरफ से विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करना।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में जैसा परिकल्पित है, उसके हिसाब से मेक इन इण्डिया सकल घरेलू उत्पाद को 25 प्रतिशत का योगदान और 2022 तक 10 करोड़ नौकरियाँ दे सकता है।
- भारत में कामगारो/बेरोजगारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ताकि वे उचित रोजगार पा सके।
- रचनात्मक संभावना के दोहन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के क्रम में स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड इंडिया अभियान की घोषणा की गई।
- भारत में नवाचार और स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रोत्साहन मंच शुरू प्रारम्भ किया गया, जिसका नाम एआईएम (अटल इनोवेशन मिशन) है। इसके अतिरिक्त, एक तकनीकी–वित्तीय ऊष्मायन एवं सुगमता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसका नाम एसईटीयू (सेल्फ एम्पलॉयड ऐड टैलेंट यूटिलाइजेशन) है।

- लघु व मध्यम क्षेत्रों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और स्टार्ट–अप्स एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे–
  - एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम को वित्त पोषण के लिए सिडबी (SIDBI) के तहत इंडिया एस्पाइरेशन फंड की भी स्थापना की गई है।
  - उदार शर्तों पर भारतीय एसएमई कंपनियों को शर्त आधारित अल्पावधि ऋण व आभाषी इक्विटी देने के लिए सिडबी (एसआईडीबीआई) मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल इन्टरप्राइजेज (स्माइल) का शुभारंभ किया गया।
  - सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक/एनबीएफसी/कॉपरेटिव बैंकों के विकास व पुनर्वितीयन के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा कई अन्य सेवाऐं उपलब्ध कराती है, जैसे वित्तीय साक्षरता और सूचना एवं कुशलता की खाई को भरने का काम। यह उसका 'क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण' है।

यहाँ पर इस योजना का दृष्टिकोण तथा इसे सफल बनाने हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को रेखांकित किया जाना अपेक्षित है। स्वदेशी तकनीक से जो विकास सम्भव हो रहे है उन्हें समझना भी आवश्यक है। मेक इन इण्डिया वर्जन 2.0 के अन्तर्गत सरकार द्वारा चैम्पियन क्षेत्रों (Champion Sector) की पहचान की गई है। जिनमें वैश्विक स्तर पर चैम्पियन बनने की क्षमता है। इसके अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्र है–पूंजीगत वस्तुएँ, वाहन, प्रतिरक्षा एवं अन्तरिक्ष, उड्डयन, जैव तकनीक, औषधी, इलेक्ट्रानिक, डिजाइन एवं विनिर्माण, चर्म एवं जूता, वस्त्र एवं पोषाक, खाद्य प्रसंस्करण, जवाहरात एवं आभूषण, नवीनीकरण एवं उर्जा निर्माण, जहाजरानी, रेलवे आदि है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को स्पष्ट करना है। भारतीय व्यापार की अन्य देशों में क्या पहचान है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्यों को इंगित करना भी उचित होगा। स्टार्ट अप कौशल विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास में क्या योगदान है।

जिन उद्योगपतियों ने इसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया है उनका यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा।[4]

fot; 'k[kj 'kek % पेटीएम के संस्थापक एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा का नाम 2017 में समाचारों में आया। इस वर्ष उनकी कंपनी का तेजी से विकास हुआ और थोड़े समय में ही यह ग्लोबल ब्रांड बन गया। नोटबंदी से उनका भाग्य चमका क्योंकि नोटबंदी से कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला और शर्मा द्वारा 2010 में प्रारम्भ किए गए पेमेंट गेटवे का बाजार मूल्य बढ़ा। करीब 20 करोड़ यूजर के साथ उनकी कंपनी ने भारत में गहरी जड़ें जमा लीं। आज उनकी कंपनी की पूंजी फ्लिपकार्ट की पूंजी के करीब है। उनकी कंपनी उन 11 कंपनियों में है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक खोलने का लाइसेंस दिया है। उनकी कंपनी भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने कनाडा में भी काम प्रारम्भ किया है।

ed'k vckuh % रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 38 अरब डॉलर (लगभग दो लाख 47 हजार करोड़ रुपए) है। वह लगातार 10वें वर्ष भारत के सबसे रईस लोगों में शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने 2016 में रिलायंस जिओ इंफोकॉम की शुरुआत की और उसके लगभग 20 करोड ग्राहक बना लिए हैं। उनकी जिओ इंफोकॉम के लिए आईपीओ लाने की योजना है। मुकेश अंबानी का मानना है कि 2030 तक भारत के 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना है। उनका मानना है कि आने वाला समय कनेक्टिविटी और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस का है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वह पांच करोड़ घरों को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क जिओ गीगा फाइबर के जरिये कनेक्ट करेंगे और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में शीर्ष पांच देशों में भारत को स्थान दिलाएंगे।

fnyhi 'kk?koh % सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी का नाम हाल में समाचारों में रहा। अमेरिका द्वारा भारतीय दवा उद्योग पर नियंत्रण लगाने का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ा। सन फार्मास्यूटिकल का बाजार मूल्य गिर गया। दिलीप शांघवी ब्लूमबर्ग के बिलिनेयर्स इंडेक्स में भारत के सबसे धनी व्यक्ति में शीर्ष से गिरकर छठे पायदान पर आ गए। उनकी कंपनी जेनेरिक दवा बनाने वाली दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी है और यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बड़ी कंपनी है। 2017 में सन फार्मा ने जापान में प्रवेश किया और रूस में अपनी मौजूदगी बढ़ाई।

vthe çeth % भारतीय उद्योगपति, निवेशक और परोपकारी अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। विप्रो का लगभग 70 प्रतिशत शेयर उनके पास है। उनका एक अपना निजी इक्विटी फंड प्रेमजीइन्वेस्ट भी है। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का 25 प्रतिशत दान करने का संकल्प लिया है। 2017 में वह विप्रो की पूंजी में नुकसान और अपनी सैलरी में कटौती को लेकर समाचारों में रहे। उनकी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम स्पोंसर करती है। इसके तहत उन लोगों को , शिक्षा पाने का अवसर दिया जाता है जो देश के सुदूर जिलों में काम करने को राजी होते हैं। वह अजीम प्रेमजी स्कूल और यूनिवर्सिटी का संचालन करते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में संतुष्टि मिलती है।

lkbjl feL=h % टाटा ग्रुप के प्रमुख रहे उद्योगपति साइरस मिस्त्री टाटा संस में कुप्रबंधन के मुद्दे को उठाने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अपील प्रस्तुत करने को लेकर 2017 में समाचारों में रहे। मिस्त्री ने अपील में टाटा संस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आर्टिकल 75 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी जिसके अनुरूप ग्रुप को निजी कंपनी में बदलने की मांग की गई थी। मिस्त्री की कंपनी की टाटा संस में 18 प्रतिशत भागीदारी है। एनसीएलटी ने मिस्त्री के विरूद्ध और टाटा संस के पक्ष में निर्णय दिया है।

lfpu vkj fcUuh cly % 2017 में सचिन और बिन्नी बंसल ने बेहतर संचालन के लिए अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट को पुनर्गठित किया। इसके तहत बिन्नी को ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया जबकि सचिन बंसल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहे। कंपनी के दोनों प्रोमोटरों ने अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए 2017 में कई कदम उठाए। फ्लिपकार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सक्लुसिव क्लाउड प्लेटफार्म माइक्रोसॉफ्ट अज्युरे के जरिये ग्राहकों को बेहतर सुविधा के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया। फ्लिपकार्ट का कॉम्पटीशन एमेजान से है। फ्लिपकार्ट ने निवेशकों के जरिये तीन अरब डॉलर (करीब 20,000 करोड़ रुपए) जुटाए हैं। 2018 में सचिन और बिन्नी ने अपनी कंपनी का अधिकांश नियंत्रण अमेरिका की प्रमुख कंपनी वालमार्ट को सौंप दिया।

vkpk;Z cky—".k % पतंजलि के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में 2017 में कंपनी ने 170 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। बाबा रामदेव के साथ मिलकर प्रारम्भ की गई पतंजलि में बालकृष्ण की भागीदारी 98.6 प्रतिशत है। दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित है। पतंजलि प्रमुख ग्लोबल ब्रांडों को चुनौती दे रही है और फास्ट मूविंग कॉनज्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में यह अभी केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर से पीछे है। बालकृष्ण गुणवत्ता वाले विभिन्न तरह के उत्पादों को पेश करने में सफल रहे हैं।

lkbjl iqukokyk % साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। वह यूरोप और अमेरिका से टेक्नोलॉजी क्रय रहे है। उनके संस्थान ने 2017 में रोटावायरस का टीका लांच किया जो भारतीय अवस्था के अनुकूल है और इसे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूनावाला महात्मा गांधी की 1931 की पेंसिल से बनाई गई दुर्लभ तस्वीर को लंदन में नीलामी में खरीदने के पश्चात् समाचारों में आए। इस तस्वीर को कलाकार जॉन हेनरी एम्शेवित्ज ने बनाया था।

jru VkVk % टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने साइरस मिस्त्री से कमान ले ली थी जिन पर उन्होंने नॉन परफॉरमेंस का आरोप लगाया था। बाद में

उन्होंने मिस्त्री की जगह टीसीएस के चंद्रशेखरन को टाटा संस का प्रमुख नियुक्त किया। मिस्त्री ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। रतन टाटा ने एनसीएलटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिये गए निर्णयों का बचाव किया। वह दो वर्षों से भी कम समय में करीब 30 स्टार्ट अप में निवेश कर समाचारों में रहे हैं।

vkuan eÇgæk % महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की पिनिन्फरिना और सांगयोंग ब्रांड के नाम से अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना है। कंपनी की 2018 में चार सस्ते ई–वाहन और ई–बसें पेश करने की भी योजना है। कई अमेरिकी ट्रैक्टर असेम्बलिंग प्लांट का संचालन कर रही कंपनी अमेरिकी बाजार में पेश करने के लिए स्व–चालित टैक्टर मॉडलों का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने यूडब्ल्यूसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप के फंड के लिए स्कोले मंडी फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया है।

mn; dkVd % कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सेबी द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉरपोरेट गवर्नेस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में स्वतंत्र निदेशकों को अधिक अधिकार देने, चेयरमैनशिप को नॉन–एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तक सीमित करने और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देने की बातें सम्मिलित हैं।

,u- pæ'k[kju% टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन पहले टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनका मानना है कि भारतीय बाजार दुनिया में सबसे तेज विकसित होने वाला बाजार बनने जा रहा है और टाटा ग्रुप को भारत के आर्थिक विकास में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यह राय भी प्रकट की कि टाटा ग्रुप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उसकी कंपनियां अपनी पूरी संभावनाओं को समझ सकें। कंपनी ने इंजन बनाने वाली सीएफएम इंटरनेशनल के लीप इंजन के पास संयुक्त रूप से निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक समझौता किया है।

unu fuyd.kh % इंफोसिस के सह–संस्थापक नंदन निलेकणी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं जिसने बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार को प्रारम्भ किया और जो इसका संचालन करता है। विशाल सिक्का के हटने के बाद नंदन निलेकणी को सेवानिवृत्ति के पश्चात् वापस बुलाया गया और उन्हें फिर से इंफोसिस का चेयरमैन बनाया गया। पारंपरिक एप्लीकेशन्स डेवलपमेंट और मेंटीनेंस पर फोकस करते हुए उनसे इंफोसिस के लिए नई रणनीति बनाने की अपेक्षा है। नंदन निलेकणी और उनकी पत्नी ने बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा चलाए आंदोलन से जुड़कर संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी 50 प्रतिशत संपत्ति दान करने का संकेत दिया है।

lquhy Hkkjrh feÙky % भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का 10 प्रतिशत परोपकारी कार्यों के लिए देने का संकल्प लिया है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा दिलाने के लिए सत्य भारती यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है। उनकी कंपनी सत्य भारती स्कूल प्रोग्राम चला रही है। जिओ के आने के बाद अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए भारती एयरटेल अधिग्रहण में जुट गई है। उसने टाटा ग्रुप के वायरलेस फोन बिजनेस और भारत में टेलीनोर के संचालन का अधिग्रहण कर लिया है। भारती एयरटेल की बाजार भागीदारी अभी 40 प्रतिशत है।

vfuy vckuh % रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अभिषेक सिंघवी के विरूद्ध 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर समाचारों में रहे। सिंघवी ने अंबानी के सरकारी और निजी बैंकों से इतनी राशि के कर्ज संबंधी बयान दिया था जिसे अंबानी झूठा और छवि बिगाड़ने वाला बताते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली के आधार पर बांग्लादेश में बिजली संयंत्र लगाने का 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मुकेश अंबानी के जिओ के आने के चलते अपनी 2जी सेवा बंद करने का निर्णय किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।

latho xks;udk % गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका आईआईटी–खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन फिर से चुने गए हैं। वह दूसरी बार यह कार्य करेंगे। इससे पहले वह 2001–07 में चेयरमैन रह चुके हैं। आईपीएल टीम राइजिंग पुणे सुपरजेंट्स के मालिक रहे संजीव गोयनका एमएस धोनी को कप्तानी से हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने पर समाचारों में आए। गोयनका ग्रुप अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है और वह बिजली वितरण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। कंपनी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और बीकानेर में बिजली वितरण की फ्रेंचाइजी चलाती है।

jktho ctkt % उद्योगपति राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स के साथ साझेदारी की है जिसके साथ बजाज ऑटो लिमिटेड ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का संयुक्त रूप से निर्माण करेगी। बीएस III से बीएस IV वाहनों के होने के चलते 2017–18 की पहली तिमाही में बजाज ऑटो की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। उनकी कंपनी ने हाल ही में बाजार में नई मोटरसाइकिल लांच की है। सरकारी प्रक्रियाओं के चलते चारपहिया वाहन लांच करने की उनकी योजना में देरी हुई है।

dqekj eaxye fcM+yk % आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिड़ला। रिलायंस जिओ से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का विलय किया।

कतिपय सुझाव जिससे यह योजना भली–भांति सफलता की ओर अग्रसर होगी और भारत की बेरोजगारी और आर्थिक समृद्धि प्रकट करेगी।

वैश्विकृत औधोगिक युग में विश्व की महाशक्तियाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील है। भारत भी वैश्विकरण की प्रक्रिया में सहयोगी है। हम यह मानते है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अन्य महाशक्तियों की तुलना में उतना आगे नहीं बढा लेकिन भारत ने इस प्रतियोगिता में सराहनीय स्थान सुनिश्चित किया हैं। भारत ने जब यह अनुभव किया हमारा आयात, निर्यात कि तुलना में बहुत अधिक है जिसके कारण 'हमें घाटा दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में भारत ने 'मेक इन इंडिया–1" योजना को सन् 2014 में प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत भारत ने विभिन्न ऐसे 25 औधोगिक क्षेत्रों को चुना था, जिनके उत्पादन में वृद्धि करना था तथा इन 25 क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करके आयात से हटाकर निर्यात के क्षेत्र परिवर्तित करना था। दूसरे शब्दों में भारत को "एक मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाना था। लेकिन अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिर्पद्धा के कारण तथा विदेशी माल सस्ता मिलने के कारण "मैक इन इंडिया' योजना अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी। इसी अवधि में दुर्भाग्यवश सम्पूर्ण विश्व को "कोरोना–19'' महामारी में जकड़ लिया, जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को आघात लगा। अमेरिका एवं सम्पूर्ण यूरोप के देश इस महामारी से अत्यधिक प्रभावित हुए, दर्भाग्य से इस महामारी से बचने के लिए न कोई दवा है न ही कोई इसके उन्मूलन हेतु टीका का अविष्कार हुआ है। ऐसे अवसर पर भारत ने अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों को इस महामारी के उपचार हेतु उपलब्ध दवाओं का निर्यात किया इसके कारण भारत में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि जब भी राष्ट्र की एकता अखण्डता सप्रभुता और संस्कृति को आधात पहुँचता है तो राष्ट्रवाद का स्वतः स्फूर्त जागरण होता है। यदि वैश्वीकरण का जोर शीतयुद्ध की समाप्ति (1990) सोवियत संघ के विघटन (1991) विचारधाराओं का अंत (हैनियल बेल) इतिहास का अंत तथा एक ध्रुवीय विश्व जैसी संकल्पनाओं से खादपानी ग्रहण कर विश्व को समतल बनाने का हो तब वैश्वीकरण के विरूद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं का उठना एक स्वाभाविकता प्रक्रिया होगी किन्तु यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौधोगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करता है। पूंजी प्रवाह बढ़ाता है तथा विकास को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में पश्चिमीकरण या ''द वर्ल्ड इज फ्लैट'' का विचार हो अथवा राष्ट्र राज्य व संस्कृति रक्षा की आड़ में चरम राष्ट्रवाद का उद्भव दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए हानिकारक है। अतः इनके संतुलन पर जोर होना चाहिए ताकि विग ऑयल

जैसी कंपनी दूसरे देशों में कानूनी लूट न कर सके, न ही अरब स्प्रिंग जैसी घटना हो। यह बात सच है कि इतिहास की बढ़ती धारा को मोड़ा नहीं जा सकता इसलिए उसे अधिक पारदर्शी और जन हितैषी बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। अतः भारत ने मध्य का रास्ता खोज कर भारत में बनाओ कार्यक्रम आरम्भ किया है। चाहे अन्य देश इसे स्वदेशी को प्रोत्साहन कहे या राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाये लेकिन भारत ने विदेशी निवेश को प्राथमिकता देकर इस आरोप को भी कमजोर कर दिया है। पड़ौसी देश चीन ने भी ''मेक इन चाइना'' अपनाकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्राथमिकता प्रदान की है। स्पष्टतः निःसंकोच यह मानना होगा कि मेक इन इण्डिया योजना वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास को परवान चढ़ायेगी।

lek/kku j.kuhfr

- औधोगिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में डीजल एवं इलैक्ट्रोनिक वाहनों को लेकर अनिश्चिता को समाप्त करता। स्पष्ट दिशा–निर्देशों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाहनों की नीति को आसान बनाना।
- छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों को बढ़ावा देने हेतु मापदंडो को लचीला बनाना।
- पर्यावरणीय मानकों के स्पष्टीकरण हेतु तकनीकी विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- वित्त उपलब्धता हेतु न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुद्रा जैसी योजनाओं का विस्तार करना तथा स्टार्ट अप को बढ़ावा देना।
- नियोतोन्मुख विनिर्माण मॉडल पर ध्यान केद्रित करना।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कौशल : ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ आमूल चूल परिर्वतन लाने की आवश्यकता है।

- लेजिस्लेटिव रिसर्च एजेंसी पीआरए। की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018–19 में राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 72 फीसदी अधिक खर्च करने की उम्मीद की गई थी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले खर्च के अधिकांश निर्णय केन्द्र की सीमा से बाहर है। ऐसे में अधिकतर केन्द्रीय योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज मिशन राज्य के अधिकारियों द्वारा वास्तविक कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है।
- नौकरशाही में पेशवरों का प्रवेश एक स्वागत योग्य पहल है। हालांकि इससे नौकरशाही की मानसिकता बदलने में अधिक सहायता नहीं मिली है। इसके कुछ व्यावहारिक कारण है। पहला और प्रमुंख कारण यह है कि पेशेवरों का निजी क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है और यही उन्हें लीक से हटकर सकारात्मक परिणाम पाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की अनुपस्थिति में पेशेवर भी नौकरशाही के कामकाज करने के तरीको के अनुरूप ही काम करने लगते है और वहीं पर इस नए प्रयोग के विफल होने की आंशका बढ़ जाती है। ऐसे कई क्षेत्र है, जहाँ आमूल चूल परिर्वतन लाने की आवश्यकता है।
- हाल में आई विश्व बैंक की 2018 की कारोबार करने को सरल बनाने वाले रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीएसटी फाइलिंग में लगने वाले समय में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में कारोबारियों को कर अदायगी में लगने वाला समय लगभग 214 घटें का था, जो 2018 में 275 घंटे का हो गया। इसी रिपोर्ट में विभिन्न पैमानों पर इन्सॉल्वेसी एंड बैकरप्सी कोड के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।
- दिवालियेपन की घोषणा के बाद कर्ज नहीं लौटाने की बढ़ती परपंरा में भारत 2017 में 103वें पायदान पर था वही 2018 में भारत 108वें पायदान पर आ गया। केन्द्र सरकार को न केवल सब्सिडी जैसे संरक्षणवादी उपायों पर पुनः एक गहन विचार करने की आवश्यकता है बल्कि कुछ और मामलों में भी उदाहरण स्वरूप 2016 के रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम को भी पुनः परखने की आवश्यकता है।

- स्किल डेवलमेंट मिशन के मामले में भी कई कमियां रही है, उद्योग जगत के साथ इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नही। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना का मूल उद्धेश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और स्किल डेवलपमेंट में व्यापार जगत को जोड़ना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पुरे मिशन में सरकार की तरफ से लगभग 99 फीसदी फंड की भागीदारी रही जबकि इसकी फ्लैगशिप स्कीम में भी केवल 12 फीसदी प्रशिक्षुओं को ही रोजगार मिला।
- हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस उद्योग का वृद्धि स्तर पर अधिक है और कौन से उद्योग में रोजगार की संभावना प्रबल है। कौशल प्रशिक्षण के साथ–साथ फंड के मामले में भी उद्योग जगत को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत अपने साथ जोड़ सकते हैं। इससे न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी बल्कि सरकार के वित्तीय दबाव में भी कमी आएगी। बहरहाल नीति आयोग में लगातार विशेषज्ञों की हो रही निरन्तर बैठकें इस सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के समपर्ण को दर्शाता है।

lkjr% यह कहा जा सकता है कि मेक इन इण्डिया कार्यक्रम ने भारत में स्वदेशी की भावना को प्रबल समर्थन दिया है तथा वैश्वीकरण के स्थान पर राष्ट्रीयता को पनपाया है। हमने इस कार्यक्रम के द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने चुनौती स्वीकारी थी साथ ही भारतीय उत्पादों को निर्यात करने की भी ठानी थी। दुर्भाग्य से कोविड–19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचायी है। वैश्विक महाशक्तियों ने इसके लिए चीन को उत्तरदायी माना है। इस अवधि में चीनी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। भारत ने भी चीन से दूरी बढ़ाई है तथा चीनी कम्पनियों के ठेकों को रद्ध किया है। ऐसे समय में चीन ने सीमाओं पर तनाव उत्पन्न कर दिया है, परिणामस्वरूप भारत ने कड़ा रूख अपनाते हुए मेक इन इंडिया वर्जन–2 कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारम्भ कर दिया है। इसके अन्तर्गत स्वदेशी अपनाते हुए राष्ट्रीय स्वाभीमान को प्राथमिकता दी गई है। दूसरे शब्दों में भारत आयातित वस्तुओं के निर्माण को प्राथमिकता देगा तथा स्वदेश में इस स्तर तक उत्पादन बढ़ायेगा कि उस वस्तु को निर्यात करने की स्थिति में हो जायेंगे और भारत आत्मनिर्भर हो जायेगा।

lnHk lph

1. पंत पुष्पेश : भूमंडलीकरण एवं भारत; एक्सस पब्लिकेशन हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 2016, पृ. 2
2. महर्षि राजीव : भारत–2019, मेक्ग्राहिल एजूकेशन (इण्डिया) प्रा.लि., चेन्नई–2019, पृ. 1–6–107
3. पुरी वी.के. एवं मिश्र एस.के. : भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि. मुम्बई, 2019, पृ. 110
4. महर्षि राजीव : भारत–2019, मेक्ग्राहिल एजूकेशन (इण्डिया) प्रा.लि., चेन्नई–2019, पृ. 1–11–127

❖◆❖